

बांग्लादेश में कट्टरपंथी बेलगाम

मशहूर रॉकस्टार जेम्स के कॉन्सर्ट पर हमला

ढाका, 27 दिसंबर. बांग्लादेश में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और खुले समाज को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

देश के मशहूर रॉकस्टार जेम्स के कॉन्सर्ट पर फरीदपुर में हुआ हमला सिर्फ एक संगीत कार्यक्रम में हुई हिंसा नहीं, बल्कि उस गहराती चुनौती का संकेत है, जिससे बांग्लादेश आज जुझ रहा है। जिला स्कूल की 185वीं वर्षगांठ जैसे ऐतिहासिक और शैक्षणिक अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पत्थरबाजी और अफरा-तफरी ने यह दिखा दिया कि कट्टरपंथी



ताकतें अब सांस्कृतिक आयोजनों को भी निशाना बना रही हैं। इस घटना में 20 से 25 छात्रों के घायल होने की खबर ने समाज और राजनीति दोनों को झकझोर दिया है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और दारवों ने इस हमले को इस्लामिक कट्टरपंथ से जोड़ते हुए बहस को



और तेज कर दिया है। ऐसे समय में, जब बांग्लादेश की राजनीति बदलाव के दौर से गुजर रही है और बीएनपी नेता तारिक रहमान को भविष्य के बड़े चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है, यह सवाल अहम हो गया है कि क्या आने वाला नेतृत्व कट्टरपंथी सोच पर लगाम लगाने में सक्षम होगा।

इस हिंसा में कम से कम 20 से 25 छात्र घायल हो गए। हालात को बिगड़ता देख प्रशासन ने सुरक्षा कार्रवाओं का हवाला देते हुए कॉन्सर्ट रद्द करने का फैसला लिया। आयोजन समिति के संयोजक मुस्ताफिजुर रहमान शमीम ने बताया कि डिटी कमिश्नर के निर्देश पर कार्यक्रम रोकना पड़ा, क्योंकि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी। हालांकि, अब तक प्रशासन या पुलिस की ओर से यह साफ नहीं किया गया है कि हमलावर कौन थे और उनका मकसद क्या था। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और पोस्ट में दावा किया।

सरकार ने मनरेगा को किया कमजोर

राहुल बोले- राज्यों के अधिकार छीने

नई दिल्ली, 27 दिसंबर. मनरेगा को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने मनरेगा को कमजोर कर गरीबों, दलितों, आदिवासियों और राज्यों के अधिकारों पर हमला किया है।

उन्होंने इसे पंचायती राज व्यवस्था और संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। वहीं, भाजपा ने राहुल गांधी पर विदेश यात्रा के दौरान भारत विरोधी ताकतों से जुड़ने और देश की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। भाजपा ने कहा कि राहुल के बयान एक सुनियोजित रणनीति का

भाजपा ने लोकसभा में नेता विपक्ष एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विदेशी धरती से एक बार फिर देश विरोधी कृत्यों में शामिल होने और बयान जारी करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाया है। भाजपा प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने पार्टी मुख्यालय में शनिवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में श्री गांधी की संसद सत्र के दौरान जर्मनी में ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस में भाग लेने पर निशाना साधा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यह सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस नेता श्री गांधी विदेश यात्रा पर जाते रहते हैं और वहां से भारत विरोधी बयान भी जारी करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि उनके पारिवारिक सलाहकार सैम पित्रोदा ने शुक्रवार को एक साक्षात्कार में कहा कि कांग्रेस पार्टी ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस नामक एक गठबंधन का हिस्सा है और उसी में भाग लेने के लिए राहुल गांधी जी जर्मनी गए थे।

हिस्सा हैं। दोनों पक्षों के आरोप-प्रत्यारोप से राजनीतिक माहौल और गरमा गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल ने कहा प्रधानमंत्री ने अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने गरीबों के हक पर हमला किया है और मनरेगा

के जरिए करोड़ों लोगों को मिल रहे न्यूनतम रोजगार के गारंटी के उनके हक को छीना है। श्री गांधी ने कहा मोदी सरकार ने मनरेगा खत्म कर पंचायती राज व्यवस्था में राजनीतिक हिस्सेदारी और वित्तीय पहुंच को खत्म किया है।

तृणमूल सांसद के बेटों, बहन और मां को किया गया तलब

कोलकाता, 27 दिसंबर. चुनाव आयोग (ईसीआई) ने तृणमूल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और लोकसभा की मुख्य सचिव ककोली घोष दस्तौदार के दो पुत्रों को ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावों और आपत्तियों के संबंध में उसके सामने पेश होने के लिये बुलाया है। इसकी प्रक्रिया शनिवार को शुरू हुई थी। सुश्री घोष ने नोटिस मिलने के बाद चुनाव आयोग पर पश्चिम बंगाल में पुनरीक्षण प्रक्रिया को मजबूत बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नोटिस इसलिए जारी किये गये क्योंकि उनके बेटों विश्वनाथ और बैद्यनाथ के नाम 16 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची से गायब थे। सुश्री घोष के अनुसार आयोग ने उनकी मां और

एनबीसीसी व दिल्ली सरकार का समझौता

नई, 27 दिसंबर. हालिया घटनाक्रम में एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बीच सुल्तानपुर/घिंटोरनी गांव में स्थित 42.46 एकड़ भूमि से संबंधित लंबे समय से लंबित मुकदमे के समाधान हेतु समझौता किया गया है।

समझौते का विवरण माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त बैठक के संकल्प के माध्यम से जारी किया गया है। समझौते के पश्चात, उपराज्यपाल एवं दिल्ली सरकार से बहुप्रतीक्षित अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, एनबीसीसी, घिंटोरनी, दक्षिण दिल्ली में स्थित 21.2 एकड़ के प्रमुख भूखंडको विकसित करने के लिए तत्पर है, जिससे उक्त संपत्ति से संबंधित वर्षों से चले आ रहे मुकदमे एवं



प्रशासनिक विवाद का औपचारिक रूप से समाधान हुआ है। घिंटोरनी की कुल 42.46 एकड़ भूमि को एनबीसीसीएवं जीएनसी टीडीके बीच समान रूप से विभाजित होगा। एनबीसीसीके हिस्से में 21.2 एकड़ भूमि आएगी। एनबीसीसीको अपनी भूमि हिस्सेदारी से संबंधित बकाया के निपटान हेतु भूमि व भवन विभाग, जीएनसीटीडीके को 15 करोड़ का एकमुश्त भूमि प्रीमियम तथा 15 करोड़ की एकमुश्त ब्याज राशि (150 करोड़) का भुगतान करना होगा।

उपयुक्त मदों के लिए कुल राशि लगभग 220 करोड़ होगी। एनबीसीसी, एनबीओ (2.5 एकड़) एवं डीएमआरसी (12.45 एकड़) द्वारा उपयोग में ली गई भूमि हेतु वर्ष 2025 तक प्राप्त भूमि किराया तथा प्रीमियम की राशि भी जीएनसीटीडीके अंतरित करेगा। एनबीसीसी, पहले से हस्तांतरित भूमि के हिस्से के लिए डीएमआरसीद्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम की मद में 2.82 करोड़ तथा एनबीओसे प्राप्त किसी भी प्रीमियम राशि की प्रतिपूर्ति करेगा। पूर्ण भुगतान प्राप्त होने पर जीएनसीटीडीके द्वारा 21.2x एकड़ भूमि के लिए एनबीसीसी के पक्ष में स्थायी पट्टा विलेख निष्पादित किया जाएगा।

दम घुटने से एक ही परिवार के चार लोगों की मौत, चार गंभीर

छपरा, 27 दिसम्बर. बिहार में सारण जिले के भगवान बाजार थाना क्षेत्र में एक घर में अंगीठी जलाकर सो रहे तीन मासूम बच्चे सहित चार लोगों की दम घुटने से मौत हो गई तथा चार अन्य की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस सूत्रों ने शनिवार को यहां बताया कि शुक्रवार की देर रात को अम्बिका कॉलोनी निवासी रामलखन सिंह के परिवार के आठ लोग एक ही कमरे में अंगीठी जलाकर सो गए थे। बंद कमरे में धुआं भरने के कारण सुबह तक दम घुटने से सभी लोगों की हालत बिगड़ गई। आज सुबह जब देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों ने दरवाजा तोड़ कर घर में प्रवेश किया। जहां सभी आठ लोग बेहोश मिले।

एक नजर में



सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों से पकड़े हथियार इम्फाल 27 दिसंबर. मणिपुर के विभिन्न जिलों में सुरक्षा बलों और पुलिस ने साझा अभियान चलाते हुए 25 और 26 दिसंबर को कई उग्रवादियों को गिरफ्तार किया और हथियार, गोला-बारूद, संचार उपकरण, शराब और मादक पदार्थों की भी बरामदगी की गई। सुरक्षा बलों ने इंग्फाल पश्चिम जिले में लाम्गोल गेम विलेज क्षेत्र के एक राहत शिविर में अस्थायी रूप से रह रहे तीन उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी लाम्गोल गेम विलेज जौन-तीन के लॉफेल पुलिस थाना क्षेत्र से की गई। एक अन्य अभियान में लाम्गोल गेम विलेज जौन-तीन स्थित एक फार्माहउस से एक अन्य उग्रवादी को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक मोबाइल फोन और एक आधार कार्ड बरामद किया गया।

कंबोडिया-थाईलैंड का संघर्ष विराम पर सहमति नाम्पेह 27 दिसंबर. कंबोडिया और थाईलैंड ने सीमा पर जारी तनाव को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए शनिवार दोपहर से तत्काल और पूर्ण संघर्ष विराम लागू करने पर सहमति व्यक्त की है। स्थानीय मीडिया के अनुसार दोनों देशों ने तीसरी विशेष सामान्य सीमा समिति की बैठक के बाद एक संयुक्त वक्तव्य जारी करके यह सहमति जाहिर की। यह समझौता कंबोडिया के फूम और थाईलैंड के बान पाक कार्ड अंतरराष्ट्रीय प्रवेश बिंदु पर हुआ। इसकी अध्यक्षता कंबोडिया के रक्षा मंत्री जनरल तेइ सेइहा और थाईलैंड के रक्षा मंत्री जनरल नत्फॉन नाकफनित ने की। इस दौरान आसियान देशों की एक पर्यवेक्षक टीम भी मौजूद रही। इस समझौते में कहा गया है कि दोनों देशों की सेनाएं वर्तमान स्थिति पर बनी रहेंगी।

दो साल में 14 लाख पाकिस्तानियों ने छोड़ा देश इस्लामाबाद, 27 दिसंबर. पाकिस्तान में हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं, इसका अंदाजा हालिया सरकारी रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। बीते दो वर्षों में करीब 14 लाख पाकिस्तानी नागरिक देश छोड़ चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या पढ़े-लिखे प्रोफेशनलस की है। डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट और नर्सों का तेजी से पलायन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और भविष्य दोनों के लिए गंभीर खतरे की घंटी बन गया है। रिपोर्ट सामने आते ही सरकार और सेना प्रमुख के बयानों पर तीखी बहस छिड़ गई है। पाकिस्तान के यूएन ऑफ एमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की ताजा रिपोर्ट में चौकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 14 लाख पाकिस्तान छोड़कर जाने वाले नागरिकों में 5 हजार डॉक्टर, 13 हजार अकाउंटेंट और 11 हजार इंजीनियर शामिल हैं, जो पाकिस्तान में बढ़ते ब्रेन ड्रेन की गंभीर तस्वीर पेश करते हैं।

अगले 5 वर्ष की योजना राष्ट्रव्यापी संपर्क सुविधा में सुधार और भीड़भाड़ कम करने पर जोर

प्रमुख शहरों में ट्रेनों का संचालन होगी दोगुनी

नईदिल्ली, 27 दिसंबर. यात्रा की मांग में लगातार हो रही तीव्र वृद्धि को देखते हुए, अगले 5 वर्षों में प्रमुख शहरों की नई रेल गाड़ियों के संचालन की क्षमता को वर्तमान स्तर से दोगुना करना आवश्यक है। आगामी वर्षों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा। वर्ष 2030 तक संचालन क्षमता को दोगुना करने के लिए निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे। इन्हें टर्मिनलों को अतिरिक्त प्लेटफॉर्म, स्टेबलिंग लाइन, फिट लाइन और पर्याप्त शॉटिंग सुविधाओं से सुसज्जित



करना। शहरी क्षेत्र में और उसके आसपास नए टर्मिनलों की कोंचिंग कॉम्प्लेक्स सहित रखरखाव सुविधाएं। विभिन्न स्थानों पर रेल गाड़ियों की बढ़ती संख्या को व्यवस्था करने के लिए यातायात सुविधा कार्यों, सिग्नलिंग उन्नयन और मल्टीट्रैकिंग के माध्यम से अनुभागीय क्षमता में वृद्धि करना।

देश के 48 प्रमुख शहरों की एक व्यापक योजना विचाराधीन है। इस योजना में निर्धारित समय सीमा के भीतर रेल गाड़ियों की संचालन क्षमता को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नियोजित, प्रस्तावित या पहले से स्वीकृत कार्यों को शामिल किया जाएगा। क्षमता को वर्ष 2030 तक दोगुना करने की योजना है, लेकिन यह आशा है कि अगले 5 वर्षों में क्षमता में क्रमिक वृद्धि की जाएगी ताकि क्षमता वृद्धि के लाभ तुरंत प्राप्त किए जा सकें। इससे आने वाले वर्षों में यातायात को बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

केंद्रीय रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, हम यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए विभिन्न शहरों में कोचिंग टर्मिनलों का विस्तार कर रहे हैं और अनुभागीय एवं परिचालन क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। इस कदम से हमारे रेलवे नेटवर्क का उन्नयन होगा और राष्ट्रव्यापी संपर्क सुविधा में सुधार होगा। अहमदाबाद स्टेशन पर ट्रेनों का लोड कम होगा, संचालन होगा।

मजदूरों के अधिकार पहले से अधिक सशक्त मोदी सरकार ने बढ़ाई 125 दिन की रोजगार गारंटी : शिवराज

नई दिल्ली, 27 दिसंबर. केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ग्रामीण रोजगार, ग्राम पंचायत के अधिकार और मजदूरों की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस सहित विपक्ष द्वारा फैलाया जा रहा भ्रम पूरी तरह तथ्यों से परे और भ्रामक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने विकसित भारत- जी राम जी योजना के माध्यम से ग्रामीण भारत और मजदूरों के अधिकारों को पहले से अधिक मजबूत किया है, न कि कमजोर। शिवराज सिंह ने कड़े



शब्दों में कहा कि कांग्रेस के राज में तो मनरेगा योजना भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी थी और अब हम पूरी पारदर्शिता के साथ विकसित भारत- जी राम जी योजना लाए हैं, जिससे देशभर के मजदूरों को वास्तविक लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस का शोर सिर्फ राजनीतिक है डू कांग्रेस के पास न नीयत थी, न नीति। यह वही कांग्रेस है, जिसने

चुनावी फायदे के लिए महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा। यह वही कांग्रेस है, जिसने समय-समय पर मनरेगा का बजट कम किया। यह वही कांग्रेस है, जिसने मजदूरी फ्रिज की, और आज कांग्रेसी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार ने मांग-आधारित रोजगार को कम नहीं, बल्कि और मजबूत किया है। उनके अनुसार वीबी-जी राम जी अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों की जगह 125 दिनों की वैधानिक रोजगार-गारंटी दी जा रही है, जिससे मजदूरों को अधिक दिन का सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित होगा।

उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 45 करोड़ रुपए वापस दिलवाए

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने देश भर में उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रभावी, समयबद्ध और मुकदमेबाजी से पहले निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए आठ महीनों में 31 क्षेत्रों में 45 करोड़ रुपये की राशि उपभोक्ताओं को वापस दिलवाई है। ई-कॉमर्स क्षेत्र में सबसे अधिक 32 करोड़ रुपये और यात्रा तथा पर्यटन क्षेत्र में साढ़े तीन करोड़ रुपये की राशि वापस दिलवाई गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने शनिवार को एक वक्तव्य जारी कर

कहा कि हेल्पलाइन ने इस वर्ष 25 अप्रैल से 26 दिसंबर तक आठ महीने की अवधि के दौरान 31 क्षेत्रों में राशि वापस दिलवाने के दावों से संबंधित 67,265 उपभोक्ता शिकायतों का समाधान करते हुए 45 करोड़ रुपये की राशि के वापस दिलवाई है। ई-कॉमर्स क्षेत्र में शिकायतों और वापस दिलवाई गई राशि सबसे अधिक दर्ज की गई जिसमें 39,965 शिकायतों के परिणामस्वरूप 32 करोड़ रुपये की राशि वापस दिलवाई गई। इसके बाद यात्रा और पर्यटन क्षेत्र का स्थान रहा जिसमें 4,050 शिकायतें दर्ज की गईं और 3.5 करोड़ रुपये की राशि वापस दिलवाई गई।

आज का इतिहास

- 1776 ग्वाडेलोप द्वीप में तूफान से छह हजार से अधिक लोगों की मौत।
- 1838 पंजाब के महाराज रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र दलीप सिंह का जन्म।
- 1869 पॅसिल्वेनिया के अवॉदेल में एक खदान में आग लगने से 110 लोग मरे।
- 1905 अटलांटा जीवन बीमा कंपनी की शुरुआत हुई।
- 1914 फ्रांस एवं जर्मनी के बीच माने का युद्ध प्रारम्भ।
- 1924 इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी की हत्या का प्रयास विफल।

एआई से बदली वैश्विक अर्थव्यवस्था

नईदिल्ली, 27 दिसंबर. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) वैश्विक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा दोनों बदल रही है। चीन ने 2025 में एआई उद्योग को एक ट्रिलियन युआन से अधिक के कारोबार तक पहुंचाकर तकनीकी नवाचार में अपनी मजबूत स्थिति साबित की है।

वहीं भारत भी एआई और औद्योगिक स्वचालन के जरिए तकनीकी विनिर्माण के नए युग में प्रवेश कर चुका है। स्मार्ट फैक्ट्रियां, मशीन लर्निंग, रियल-टाइम एनालिटिक्स और स्वचालित सप्लाई चैनल हैं। अधिक प्रतिस्पर्धी बना रही हैं। पीएलआई योजनाओं, एफडीआई और इंडिया एआई मिशन के सहारे भारत वैश्विक तकनीकी विनिर्माण हब बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। चीन में एआई इंडस्ट्री कारोबार साल 2025 में एक ट्रिलियन युआन से ज्यादा का हुआ। चीन ने 2025 में औद्योगिक तकनीकी नवाचारों में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। वहां अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) उद्योग का आकार एक ट्रिलियन युआन (करीब 12.78 लाख करोड़ रुपये) से अधिक का हो गया है। यह जानकारी उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में दी गयी। चीन के उद्योग मंत्रालय के अनुसार, 2025 में बढ़े औद्योगिक उद्यमों के कुल मूल्यवर्धन में पिछले वर्षों की तुलना में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।



मंत्रालय ने एंजेंडा 2026 के तहत उभरते और भविष्य के उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना तैयार की है। इसमें एआई अनुसंधान के साथ-साथ इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर, डायोमेट्रिसिन लो-एन्टीड्यूड इकोनॉमी जैसे प्रमुख क्षेत्रों के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष जनवरी से नवंबर के बीच उच्च तकनीक और उपकरण निर्माण उद्यमों के मूल्यवर्धन में 9 प्रतिशत से अधिक की शानदार वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। चीन ने वर्तमान में 60 लाख से अधिक नवाचार-संचालित लघु एवं मध्यम आकार के उद्यम विकसित कर लिए हैं।

एआई-आधारित सप्लाई चैन सिस्टम लागत घटाने और लीड टाइम बढ़ाने में सहायक साबित हो रहे हैं। वहीं, आईआईटी मद्रास-बॉश अध्येन (2025) बताता है कि मशीन लर्निंग से प्रोटोटाइप विकास समय 60 प्रतिशत तक घटा और विफलता दर में 30 प्रतिशत से अधिक कमी आई। कार्यबल और स्थिरता का नया युग-ईवाइ इंडिया वर्कफोर्स टैंडस रिपोर्ट 2025 के मुताबिक, भारत की 52 प्रतिशत विनिर्माण कंपनियां एआई-आधारित रिस्क डेवलपमेंट शुरू कर चुकी हैं। एआई और स्वचालन अब नौकरियां खत्म नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें अधिक रणनीतिक और विश्लेषणात्मक बना रहे हैं।

बदलता भारत का तकनीकी विनिर्माण भविष्य

एआई का प्रयोग भारत सहित में पूरी दुनिया अब लगातार बढ़ता जा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और औद्योगिक स्वचालन के संगम से प्रेरित होकर भारत का तकनीकी विनिर्माण उद्योग अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। स्मार्ट फैक्ट्रियां, पूर्वानुमान विश्लेषण और रियल-टाइम निर्णय क्षमता ने विनिर्माण को पहले से कहीं अधिक चुस्त, विस्तार योग्य और परिणाम-केन्द्रित बना दिया है। सरकार की पीएलआई योजनाओं, बढ़ते एफडीआई प्रवाह और मई 2025 में शुरू हुए इंडिया एआई मिशन के सहयोग से भारत उदर इलेक्ट्रॉनिक्स और एम्बेडेड सिस्टम विनिर्माण में वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। एम्बेडेड तकनीक, स्मार्ट कंट्रोलर और आईओटी-आधारित समाधानों में काम कर रही इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियां इस बदलाव की अगुवाई कर रही हैं। एआई बना विनिर्माण का नया इज्जत-एआई अब केवल प्रयोक्ताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन, रियल-टाइम क्वालिटी इश्यूक्शन और भविष्यसूचक रखरखाव में अहम भूमिका निभा रहा है। आईडीसी इंडिया के अनुसार, लगभग 486 भारतीय निर्माता कम से कम एक प्रमुख कार्य में एआई को अपना चुके हैं।